



International Year
of Cooperatives

Cooperatives Build a Better World



माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह, बीपीआरएंडडी की समीक्षा बैठक लेते हुए
Hon'ble Union Minister of Home Affairs and Cooperation, Shri Amit Shah, taking a review meeting of BPR&D

खण्ड VI : अंक XV जनवरी – मार्च, 2025
Vol: VI : Issue XV January - March, 2025

बीपीआरएंडडी बुलेटिन BPR&D Bulletin

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
Bureau of Police Research & Development, Ministry of Home Affairs, Govt. of India

महानिदेशक की कलम से.....

मुझे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो त्रैमासिक समाचार बुलेटिन का जनवरी-मार्च 2025 अंक प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसमें तिमाही के दौरान ब्यूरो और उसके प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा की गई प्रभावशाली पहलों और सार्थक कार्यों की विस्तृत शृंखला का विवरण दिया गया है।

दिनांक 8 जनवरी, 2025 को माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने ब्यूरो मुख्यालय का दौरा किया और संगठन के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने देश के पुलिस संगठनों का समर्थन करते हुए, गृह मंत्रालय के लिए एक मजबूत और विश्वसनीय थिंक टैंक के रूप में ब्यूरो की प्रभावशीलता, उपयोगिता और विकास को और बढ़ाने के लिए कुछ निर्देश दिए। ब्यूरो ने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा दिए गए आदेशों को पूरा करने के लिए गंभीरता से कार्रवाई शुरू कर दी है।

जनवरी माह में उल्लेखनीय क्षमता निर्माण गतिविधियों में क्वांटम कंप्यूटिंग पर सेमिनार का आयोजन, पुलिसिंग में अग्रणी प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के हमारे उद्देश्यों को रेखांकित करना, उड़ीसा, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश में नए आपराधिक कानून 2023 पर जेल अधिकारियों के संवेदीकरण के लिए जेल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल थे। ब्यूरो ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार नराकास की 5वीं छमाही बैठक भी आयोजित की।

फरवरी माह में ब्यूरो के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में क्षेत्रीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य पुलिस चुनौतियों की पहचान करना और उन पर विचार-विमर्श करना था। पुलिसिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्षेत्रीय सम्मेलन, तटीय पुलिस स्टेशनों के लिए एसओपी के संशोधन पर कार्यशाला, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग आधारित पाठ्यक्रम, मानव तस्करी विरोधी कार्यशाला और डिजिटल साक्ष्य को संभालने पर पाठ्यक्रम बीपीआरएंडडी द्वारा की गई अन्य प्रमुख गतिविधियां थीं।

मार्च माह के दौरान, ब्यूरो द्वारा प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें – आईआरएस के 78वें बैच हेतु राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा मॉड्यूल, अभियोजन निदेशालय की स्थापना के लिए कार्यशाला, पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन 2024 की सिफारिश संख्या 14 पर बैठक, पुलिस बैंड द्वारा उपयोग किए जाने वाले बैंड वाद्ययंत्रों का स्वदेशीकरण, शामिल हैं।

मैं इन पहलों की सफलता में योगदान देने वाले सभी अधिकारियों, विशेषज्ञों और प्रतिभागियों की हार्दिक सराहना करता हूँ। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ईमानदारी, सहानुभूति और व्यावसायिकता के आधारभूत मूल्यों द्वारा निर्देशित, अनुसंधान, नवाचार और सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना जारी रखेंगे।

महानिदेशक
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा बीपीआरएंडडी के कार्यों की समीक्षा

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने दिनांक 08.01.2025 को ब्यूरो मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। महानिदेशक, श्री राजीव कुमार शर्मा ने ब्यूरो की गतिविधियों और चल रहे/पूर्ण हो चुके कार्यों के बारे में मंत्री महोदय को जानकारी दी और आगे की योजनाओं को बताया। मंत्री महोदय ने इन पर अपना दृष्टिकोण साझा किया और कुछ मुद्दों पर दिशा-निर्देश दिए।

महोदय ने कहा कि ग्रीन जेल की अवधारणा को मॉडल जेल के हिस्से के रूप में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, एनसीआरबी और जेल अधिकारियों तथा फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिकों को शामिल करते हुए एक संरचना बनाने पर जोर दिया तथा कहा कि महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम योजना के प्रभावों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए।



उन्होंने पुलिसिंग, जांच और अभियोजन में वैश्विक रुझानों से अवगत रहने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। साथ ही, अनुसंधान और विकास के लिए विदेशी संस्थानों के साथ सहयोग करने का सुझाव दिया और गृह मंत्रालय के एजेंडे एवं राष्ट्रीय पुलिसिंग आवश्यकताओं के बीच वांछित संरेखण सुनिश्चित किया जाए ताकि इस पर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने पुलिस स्टेशनों के मानकीकरण और एकरूपता के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने, सीसीटीवी विनियमन के लिए एक आदर्श कानून विकसित करने और केंद्रीय एजेंसियों एवं विभिन्न राज्यों से डेटा साझा करने पर जोर दिया। नए आपराधिक कानूनों के महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने तकनीकी साक्ष्यों के उपयोग को बढ़ाने, गवाहों पर निर्भरता कम करने और मुकदमों में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।

उन्होंने पुलिसिंग की चुनौतियों का अध्ययन करने और समाधान खोजने के लिए तकनीकी संस्थानों के साथ नेटवर्क बनाने का आग्रह किया, जिससे सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण थिंक टैंक विकसित किया जा सके।



यूएसआई और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के बीच सहयोग



महानिदेशक, ब्यूरो, महानिदेशक, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (यूएसआई), नई दिल्ली को एक मोमेंटो प्रस्तुत करते हुए

यूएसआई के साथ सहयोग स्थापित करने के लिए दिनांक 10.01.2025 को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो मुख्यालय में महानिदेशक, ब्यूरो, श्री राजीव कुमार शर्मा और महानिदेशक, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (यूएसआई), नई दिल्ली, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) बी.के. शर्मा के बीच एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में ब्यूरो के अपर महानिदेशक, निदेशक (एनपीएम), उप निदेशक (प्रशिक्षण) और उप निदेशक (प्रशासन और आरएंडसीए) तथा USI के अधिकारियों ने भाग लिया। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (USI) नई दिल्ली स्थित एक राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा सेवा थिंक टैंक है।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारतीय संयुक्त सेवा संस्थान (USI) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों से संबंधित पाठ्यक्रमों के संचालन और सहयोग के तरीकों पर विचार करने के लिए ब्यूरो को एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

ब्यूरो मुख्यालय में "पुलिस से संबंधित चुनौतियों और प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन" पर बैठक

दिनांक 10.01.2025 को ब्यूरो मुख्यालय में महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की अध्यक्षता में एक हाइब्रिड बैठक आयोजित की गई, जिसमें सी-डैक, आईआईआईटी इलाहाबाद, DRDO (Low Intensity Conflicts), SVPNPA, NEPA और TISS, मुंबई के प्रतिनिधियों और ब्यूरो मुख्यालय के सभी प्रभागों के निदेशकों ने भी भाग लिया। बैठक में चुनौतियों और प्रौद्योगिकियों से संबंधित पुलिस संस्थानों और संगठनों के साथ भविष्य के सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की गई।



महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो बैठक की अध्यक्षता करते हुए

साइबर अपराध जांच पर DSI पाठ्यक्रम के दौरान ड्रोन सिमुलेशन अभ्यास आयोजित

सीडीटीआई, चंडीगढ़ ने दिनांक 30.12.2024 से 10.01.2025 तक साइबर अपराध जांच पर एक डीएसआई पाठ्यक्रम आयोजित किया, जिसमें क्षेत्रीय राज्यों से उप निरीक्षक से लेकर उप पुलिस अधीक्षक रैंक के 27 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। डिजिटल साक्ष्य हैंडलिंग और डिजिटल उपकरणों से डेटा निकालने, ड्रोन सिस्टम का परिचय और ड्रोन सिस्टम से आवश्यक जानकारी निकालने की प्रक्रिया पर व्यावहारिक सिमुलेशन पर सत्र आयोजित किए गए। प्रतिभागियों ने फॉरेंसिक उपकरणों का प्रदर्शन देखने के लिए सीएफएसएल-कंप्यूटर फॉरेंसिक डिवीजन का भी दौरा किया।



ड्रोन सिमुलेशन अभ्यास के दौरान प्रतिभागी

02 सप्ताह के पाठ्यक्रम के दौरान, 02 प्रतिष्ठित संकाय सदस्य श्री मुकेश चौधरी, साइबर विशेषज्ञ, जयपुर और श्री निशीत दीक्षित, एडवोकेट एवं साइबर विशेषज्ञ, ने नेटवर्किंग- वीपीएन/प्रॉक्सी सर्वर, वीओआईपी, सूचना एकत्रीकरण, आभासी कंप्यूटर अपराध और साइबर गश्त, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और डिजिटल साक्ष्य से निपटने में आने वाली चुनौतियों और अदालतों में इनकी स्वीकार्यता पर सत्र आयोजित किए।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (न.रा.का.स.), दक्षिण दिल्ली-1 की पांचवी छमाही बैठक



नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पांचवी छमाही बैठक

कार्यालयों में हिंदी में किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की गई। बैठक में डॉ वंदना शर्मा, उप निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के द्वारा एक प्रस्तुति के माध्यम से मलेरिया संस्थान में राजभाषा के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने के लिए किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा दिया गया।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री रवि जोसेफ लोक्कू, अपर महानिदेशक ने समिति के सदस्य कार्यालयों में राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए अपनाई जा रही उत्तम कार्यप्रणालियों को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित किया तथा सदस्य कार्यालयों द्वारा आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत कर उनका मनोबल बढ़ाया।

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (न.रा.का.स.), दक्षिण दिल्ली-1 का अध्यक्ष कार्यालय बनाया गया है, जिसके अंतर्गत कुल 75 सदस्य कार्यालय हैं। निर्देशानुसार अध्यक्ष कार्यालय द्वारा प्रत्येक छमाही (जनवरी और अगस्त) न.रा.का.स. के सदस्य कार्यालयों के लिए बैठक का आयोजन किया जाता है।

इसी कड़ी में दिनांक 22.01.2025 को अपर महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की अध्यक्षता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (न.रा.का.स.) की पांचवी छमाही बैठक का ब्यूरो मुख्यालय में आयोजन किया गया, जिसमें सदस्य कार्यालयों से कुल 124 कार्यालय प्रमुख/ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सदस्य



अपर महानिदेशक, निदेशक (एसपीडी), उप निदेशक (एसपीडी) और संयुक्त निदेशक, गृह मंत्रालय मंच पर बैठक के दौरान

“मुझे अपने कांस्टेबल को क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में क्या बताना चाहिए और क्या मुझे ऐसा करना चाहिए” पर सेमिनार

दिनांक 30.01.2025 को सीडीटीआई, जयपुर में “मुझे अपने कांस्टेबल को क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में क्या बताना चाहिए और क्या मुझे ऐसा करना चाहिए” विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों, कानूनी प्रशिक्षुओं और मणिपाल विश्वविद्यालय और जेके लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय के छात्रों सहित 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने क्वांटम कंप्यूटिंग के मूल सिद्धांतों, साइबर सुरक्षा, एन्क्रिप्शन और डिजिटल फॉरेंसिक पर इसके संभावित प्रभाव, तथा इस बात पर चर्चा की कि क्या कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इसकी प्रगति के लिए चिंतित होना चाहिए।

सेमिनार में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि किस प्रकार क्वांटम कंप्यूटर उत्कृष्ट एन्क्रिप्शन को तोड़ सकते हैं, जिससे सुरक्षित संचार और संवेदनशील डेटा संरक्षण को खतरा पैदा हो सकता है। वक्ताओं ने संभावित लाभों जैसे कि तीव्र डेटा विश्लेषण, बेहतर पूर्वानुमानात्मक पुलिसिंग, तथा साइबर खतरों से निपटने के लिए उन्नत क्रिप्टोग्राफिक समाधान पर भी विस्तार से चर्चा की।



निदेशक सीडीटीआई, जयपुर अपने बिन्दु प्रस्तुत करते हुए

तटीय पुलिस स्टेशनों के लिए SOP में संशोधन पर कार्यशाला

दिनांक 03.02.2025 को, तटीय पुलिस स्टेशनों के लिए SOP में संशोधन के संबंध में ब्यूरो मुख्यालय में एक हाइब्रिड बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अपर महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने की। बैठक में बीएसएफ और ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में बीएसएफ जल विंग की भूमिका और तटीय पुलिस स्टेशनों के साथ समन्वय पर चर्चा की गई। तटीय पुलिस के लिए संशोधित SOP में बीएसएफ की जल विंग की भूमिका और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र और गुजरात के सर क्रीक क्षेत्र में इसकी तैनाती, तटीय पुलिस के साथ समन्वय और तटीय पुलिस, भारतीय तटरक्षक और भारतीय नौसेना के साथ संचार योजना को शामिल किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 06.02.2025 को हुई दूसरी कार्यशाला में भारत के तटीय पुलिस स्टेशनों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर भी सभी हितधारकों के साथ चर्चा की गई। कार्यशाला के दौरान उभरे बिन्दुओं को तटीय पुलिस स्टेशनों के लिए संशोधित SOP में शामिल किया गया।



अपर महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन

सी.टी.टी.आई, हैदराबाद द्वारा स्कूली बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम



जागरूकता कार्यक्रम का समूह फोटोग्राफ

सी.टी.टी.आई, हैदराबाद द्वारा केन्द्रीय विद्यालय-II उप्पल, हैदराबाद के विद्यार्थियों के लिए "दुर्व्यवहार की घटनाओं की रिपोर्ट कैसे करें (गुड टच-बैड टच)" विषय पर दिनांक 11.02.2025 को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 76 छात्राओं और 02 शिक्षकों ने भाग लिया। जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों और युवा वयस्कों को सुरक्षित और असहज शारीरिक स्पर्श के बीच अंतर करना सिखाना

है तथा बच्चों को अपने शरीर को समझने, व्यक्तिगत सीमाएँ बनाने और जब वे असहज महसूस करते हैं तो बोलने में मदद करना है।

ब्यूरो मुख्यालय में 'मानव तस्करी विरोधी' (AHT) पर कार्यशाला

श्री रवि जोसेफ लोक्कू, अपर महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की अध्यक्षता में दिनांक 14.02.2025 को, विभिन्न राज्यों, यूटीएफ, सीएपीएफ, सीपीओ और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 30 अधिकारियों ने मानव तस्करी विरोधी पर आयोजित एक कार्यशाला में भाग लिया। विषय विशेषज्ञ श्री पीएम नायर ने सुझाव दिया कि हितधारकों को दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान (ASK) मॉडल पर जोर देते हुए उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा NGOs के साथ समझौता ज्ञापन एक वर्ष के लिए होना चाहिए। उन्होंने AHT मामलों को संगठित अपराध के रूप में मानने, जांच के लिए राज्यों के बीच संबंध स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से पहले NGOs की योग्यता का उचित सत्यापन किया जाए।



श्री राजीव कुमार शर्मा, महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए

“आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों में डिजिटल साक्ष्य का संचालन” पर पाठ्यक्रम

सीडीटीआई चंडीगढ़ ने दिनांक 17.02.2025 से 21.02.2025 तक “आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों में डिजिटल साक्ष्य का संचालन” विषय पर 5 दिवसीय पाठ्यक्रम का आयोजन किया। इस पाठ्यक्रम में डिजिटल फोरेंसिक में अस्थिर मेमोरी, भुगतान गेटवे की जांच, हैशिंग, इमेजिंग, मेटाडेटा विश्लेषण, आर्थिक अपराधों में डिजिटल साक्ष्य की सराहना, बैंकिंग, आदि केस कानून, ड्रोन निगरानी और ड्रोन घुसपैठ से संबंधित विषयों को शामिल किया गया। सोशल मीडिया अपराधों और प्रॉक्सी सर्वर पर व्यावहारिक सत्र भी आयोजित किए गए। साइबर विशेषज्ञ श्री मुकेश चौधरी ने वीपीएन/प्रॉक्सी सर्वर और वर्चुअल नंबरों पर एक सत्र लिया। पुलिस उपायुक्त, पंचकुला, सुश्री हिमाद्री कौशिक, भा.पु.से. ने समापन सत्र की अध्यक्षता की और प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ अपने अनुभव साझा किए।



निदेशक, सीडीटीआई, चंडीगढ़ पुलिस उपायुक्त, पंचकुला, सुश्री हिमाद्री कौशिक को एक स्मृति चिह्न भेंट करते हुए

“Artificial Intelligence पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन

सीडीटीआई, हैदराबाद ने दिनांक 18.02.2025 से 19.02.2025 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया। हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त, श्री सी.वी. आनंद, भा.पु.से. ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर प्रकाश डाला और बताया कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर में उद्योगों को बदल रहा है, दक्षता बढ़ा रहा है और तेजी से डेटा-संचालित निर्णय लेने में सक्षम बना रहा है। उन्होंने AI की परिवर्तनकारी क्षमता और भारत AI मिशन पर विस्तार से चर्चा की, जो भारत के AI पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है, जिसे न केवल अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, बल्कि वैश्विक AI परिदृश्य को आकार देने में भारत को प्रमुखता से स्थापित करना है। इस सम्मेलन में आईआईटी-हैदराबाद, आईएसबी-हैदराबाद, AI उद्योग कंपनियों के सीईओ और आंध्र प्रदेश पुलिस और सी-डैक के अधिकारी शामिल हुए। समापन सत्र में मुख्य अतिथि श्री अमित गर्ग, ने फ्रांस में हाल ही में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट पर प्रकाश डाला, जहां प्रधानमंत्री ने डीप फेक, गलत सूचना और साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए एक गवर्नेंस मॉडल का आह्वान किया।



मुख्य अतिथि, श्री सी.वी. आनंद, आई.पी.एस.



सीडीटीआई, हैदराबाद में आयोजित ‘AI’ पर क्षेत्रीय सम्मेलन के प्रतिभागियों का समूह फोटोग्राफ

ब्यूरो मुख्यालय में पुलिस बैंड द्वारा उपयोग किए जाने वाले बैंड वाद्ययंत्रों के स्वदेशीकरण पर कार्यशाला

दिनांक 19.02.2025 को नई दिल्ली में ब्यूरो मुख्यालय में सी.ए.पी.एफ./पुलिस बैंड द्वारा उपयोग किए जाने वाले बैंड उपकरणों के स्वदेशीकरण का अध्ययन करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। बैंड उपकरणों का अध्ययन करने और स्वदेशीकरण की व्यवहार्यता पर सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए सी.ए.पी.एफ. और बीपीआरएंडडी के सदस्यों वाली समिति का गठन किया गया था।

दिनांक 06.03.2025 को, समिति ने बैंड निर्माण कंपनियों के साथ बातचीत करने के लिए ब्यूरो के उप महानिरीक्षक (आधुनिकीकरण) के नेतृत्व में मेरठ का दौरा किया। अध्ययन में पुलिस ब्रास और पाइप बैंड के लिए भारत में निर्मित संगीत वाद्ययंत्रों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया और भारत में ऐसे उपकरणों के निर्माण की संभावना का पता लगाया गया।

दिनांक 19.03.2025 को, ब्यूरो मुख्यालय में सी.ए.पी.एफ./पुलिस बैंड द्वारा उपयोग किए जाने वाले बैंड उपकरणों और स्वदेशीकरण की दिशा में आगे बढ़ने के तरीके का अध्ययन करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। निर्माताओं ने अपने भारत निर्मित उपकरणों का प्रदर्शन किया और बैंडमास्टरों से फीडबैक प्राप्त किया गया। आगे के विचार-विमर्श और कार्रवाई के लिए 'मेक इन इंडिया' के रूप में निर्मित की जा सकने वाली वस्तुओं की एक सूची तैयार की गई।



कार्यशाला के दौरान अधिकारीगण



मेरठ, उ. प्र. स्थित बैंड निर्माण कंपनी में दौरे के दौरान अधिकारीगण

क्षेत्रीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस कार्यशाला का आयोजन

दिनांक 20.02.2025 को एक दिवसीय क्षेत्रीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों की पहचान करना तथा प्रभावी समाधान के लिए सुझाव एकत्र करना था।

सीडीटीआई, हैदराबाद के क्षेत्रीय राज्यों – तेलंगाना, पुडुचेरी, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अधिकारियों ने कार्यशाला में सक्रिय रूप से भाग लिया और पावर प्वाइंट प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला, साथ ही इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रस्तावित समाधान भी बताए।



तेलंगाना राज्य के पुलिस महानिदेशक, डॉ. जितेन्द्र, प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए



सीडीटीआई, हैदराबाद में आयोजित क्षेत्रीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के प्रतिभागियों का समूह फोटोग्राफ

मुख्य अतिथि, तेलंगाना राज्य के पुलिस महानिदेशक, श्री डॉ. जितेन्द्र, ने अपने समापन भाषण में कार्यशाला के आयोजन के लिए ब्यूरो और सीडीटीआई हैदराबाद के प्रयासों की सराहना की, जिसने उप-निरीक्षक से लेकर पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के लिए चुनौतियों और प्रस्तावित उपायों पर चर्चा करने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान किया।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग आधारित पाठ्यक्रम

8वां तीन दिवसीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग आधारित पाठ्यक्रम दिनांक 19-21 फरवरी, 2025 को ब्यूरो मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अब तक 07 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, और आंतरिक सुरक्षा में अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के विभिन्न विषयों पर 200 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

कार्यक्रम का उद्घाटन ब्यूरो के निदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा किया गया। एसएसबी के उप कमांडेंट डॉ. अजय कुमार शर्मा ने अनुभवी संकाय का नेतृत्व किया।



अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग आधारित पाठ्यक्रम के दौरान प्रतिभागी

पुलिसिंग के लिए चुनौतियों पर क्षेत्रीय सम्मेलन और अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस की पुनः संकल्पना



अतिथि वक्ता को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए

दिनांक 21.02.2025 को सीडीटीआई, जयपुर द्वारा पुलिसिंग के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने और छात्रों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के अंतर्गत एक वार्षिक सम्मेलन अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस (एआईपीएससी) के निर्णयों के आधार पर पुलिसिंग, सार्वजनिक सुरक्षा, सामुदायिक संबंधों और अपराध की रोकथाम में आधुनिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए "पुलिसिंग के लिए चुनौतियां और अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस की पुनः संकल्पना" शीर्षक से एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।

उसी दिन जयपुर के बियानी लॉ कॉलेज में नए आपराधिक कानून और साइबर सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 400 छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को डिजिटल युग में आपराधिक कानून और साइबर सुरक्षा में हालिया विकास के बारे में शिक्षित करना था।

सिविल पुलिस के सीधे भर्ती किए गए रैंकों के लिए प्रशिक्षण के मानकीकरण पर कार्यशाला

गठित समिति द्वारा सीधे भर्ती किए गए रैंकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार कर दिनांक 03.01.2025 को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता के समक्ष प्रस्तुत किया गया। गृह मंत्री जी ने समिति को छह कार्यशालाएँ आयोजित करने और मसौदा पाठ्यक्रम को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को फीडबैक और अंतिम रूप देने के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

इसी क्रम में शीर्ष समिति ने दिनांक 27 और 28 फरवरी 2025 को ब्यूरो मुख्यालय में श्री के. विजय कुमार, आईपीएस (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में उत्तरी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक पुलिस के सीधे भर्ती रैंक के लिए प्रशिक्षण के मानकीकरण पर दो दिवसीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई।



सिविल पुलिस के सीधे भर्ती किए गए रैंकों के लिए प्रशिक्षण के मानकीकरण पर कार्यशाला

नए आपराधिक कानूनों पर अंतर-कॉलेजिएट प्रतियोगिता का आयोजन

पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन के दौरान जारी निर्देशों के अनुपालन में, सीडीटीआई-हैदराबाद ने एक अंतर-कॉलेजिएट प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसका उद्देश्य वीडियो प्रस्तुतियों के माध्यम से नए आपराधिक कानूनों के बारे में कानून के छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करना था। इसमें लॉ कॉलेजों के विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनमें यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, उस्मानिया विश्वविद्यालय, पडाला रामी रेड्डी लॉ कॉलेज, केशव मेमोरियल लॉ कॉलेज, पीडेकाति लॉ कॉलेज, अनंथा लॉ कॉलेज और कॉलेज ऑफ लॉ फॉर विमेन, आंध्र महिला सभा शामिल थे। इस आयोजन के लिए कुल 87 टीमों ने पंजीकरण कराया था, जिन्हें लॉटरी सिस्टम के माध्यम से थीम आवंटित की गई थी। वीडियो जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 06.03.2025 निर्धारित की गई थी। शीर्ष 15 वीडियो को नकद पुरस्कार और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, जबकि 16वें से 20वें स्थान पर रहने वाली टीमों को सांत्वना पुरस्कार मिले। सभी प्रतिभागियों को दिनांक 08.03.2025 को प्रशंसा पत्र से भी सम्मानित किया गया। समापन समारोह में माननीय न्यायमूर्ति श्री सी.वी. रामुलु (सेवानिवृत्त) उपस्थित थे, जिन्होंने नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की और छात्रों के उत्साह और रचनात्मकता की प्रशंसा की।

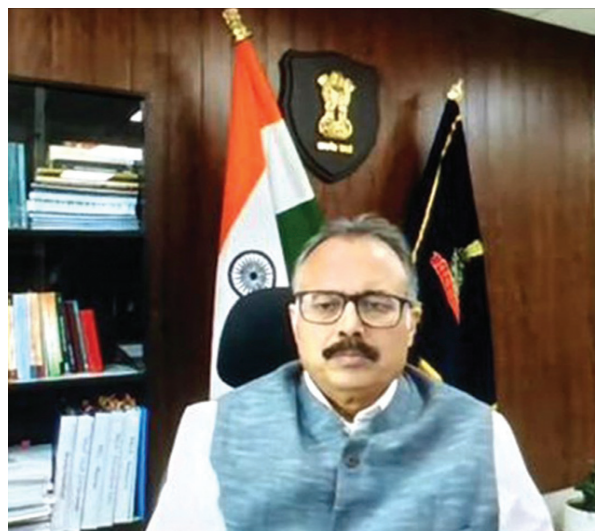


निदेशक, सीडीटीआई, हैदराबाद ने प्रतिभागियों को संबोधित किया

78वें बैच के आईआरएस अधिकारियों (OT) के लिए राष्ट्रीय एवं आंतरिक सुरक्षा मॉड्यूल

गाजियाबाद स्थित केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई) ने दिनांक 11.03.2025 से 12.03.2025 तक आईआरएस (OT) अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय एवं आंतरिक सुरक्षा मॉड्यूल पर एक पाठ्यक्रम आयोजित किया। इस पाठ्यक्रम में 144 आईआरएस (OT) अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें श्री ओ.पी. सिंह, पूर्व पुलिस महानिदेशक, यूपी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) दीपक मेहरा और कर्नल (सेवानिवृत्त), नीतीश भटनागर शामिल थे।

दिनांक 12.03.2025 को श्री राजीव कुमार शर्मा, भा.पु.से, महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने आईआरएस प्रशिक्षु अधिकारियों को अपने समापन भाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा की जटिलताओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी। देश की सुरक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि "भूमि की सुरक्षा को अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता – चाहे वह आंतरिक हो, वित्तीय हो या सुरक्षा का कोई अन्य आयाम हो। ये पहलू एक-दूसरे पर निर्भर हैं, एक क्षेत्र में विकास अनिवार्य रूप से अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इसलिए हमारे देश में सुरक्षा की बहुमुखी प्रकृति को समझने के लिए समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है।"



श्री राजीव कुमार शर्मा, भा.पु.से, महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, अपने समापन संबोधन के दौरान

दो दिवसीय पाठ्यक्रम में कुल छह सत्र थे, जिसमें मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) दीपक मेहरा ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहन चर्चा की, श्री जितेंद्र सिंह ने I4C का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया, डॉ. संदीप बेनीवाल ने आतंकवाद के वित्तपोषण पर चर्चा की, और FIU इंडिया के उप निदेशक, श्री हनी पाटोदी ने नकली नोटों और सफेदपोश अपराध पर चर्चा की। कर्नल (सेवानिवृत्त) निधिष भटनागर ने AI और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा की, और श्री ओ.पी. सिंह, (पूर्व महानिदेशक) ने भारत में आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों पर विस्तृत विवरण दिया।

अभियोजन निदेशालय की स्थापना के लिए कार्यशाला

दिनांक 25.03.2025 को महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की अध्यक्षता में ब्यूरो मुख्यालय में अभियोजन निदेशालय की स्थापना के लिए हाइब्रिड मोड में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में ब्यूरो के अपर महानिदेशक, निदेशक (प्रशिक्षण), वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जेल/कानूनी विभाग के अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हुए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 20 के अनुसार अभियोजन निदेशालय की स्थापना और कामकाज के लिए मुद्दे और चुनौतियाँ तथा न्यायपालिका और अभियोजन के संबंध में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन में चुनौतियों पर चर्चा की गई।



अभियोजन निदेशालय की स्थापना हेतु कार्यशाला में भाग लेने वाले अधिकारियों का समूह फोटो

हिंदी कार्यशाला



ब्यूरो के कार्मिक हिन्दी कार्यशाला के दौरान

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। इसके अनुपालन में, ब्यूरो मुख्यालय में दिनांक 27 मार्च, 2025 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें ब्यूरो के उन कार्मिकों की समस्याओं का समाधान किया गया जिन्हें कार्यालय के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को हिंदी में करने में कठिनाईयाँ आ रही हैं। इस कार्यशाला में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की सहायक निदेशक, श्रीमती वीनू खन्ना वक्ता थीं।

पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन 2024 की सिफारिश संख्या 14 पर बैठक

पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन 2024 की सिफारिश संख्या 14 "प्रत्येक सप्ताह, स्कूली बच्चों सहित आगंतुकों को स्थानीय पुलिस स्टेशन में विभिन्न उपकरणों और अभिलेखों के बारे में जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर स्कूलों और कॉलेजों में वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है," पर एक बैठक दिनांक 27.03.2025 को ब्यूरो मुख्यालय में आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता महानिरीक्षक/निदेशक (एनपीएम), सुश्री रुचिका ऋषि ने की।



निदेशक (राष्ट्रीय पुलिस मिशन), बीपीआरएंडडी, प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

बैठक में विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 11 अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वर्तमान में चल रही कार्यप्रणालियों और भविष्य के रोडमैप पर चर्चा की गई ताकि सिफारिशों के कार्यान्वयन में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता के लिए एक Advisory तैयार की जा सके।

सीडीटीआई, चंडीगढ़ में 'क्षेत्रीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस' का आयोजन

सीडीटीआई, चंडीगढ़ में कांस्टेबल से लेकर उप पुलिस अधीक्षक पद तक के 54 पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्रीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में दिनांक 31.03.2025 को भाग लिया। एक दिवसीय सेमिनार में 50वीं एआईपीएससी, नए आपराधिक कानून (NCL), AI और साइबर अपराध तथा जवाबदेही, पारदर्शिता और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए फोरेंसिक और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर का महत्व, एनसीएल समयसीमा, सामुदायिक पुलिसिंग, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में पुलिस, तथा जेलों में कट्टरपंथ से मुकाबला, चर्चा के मुख्य विषयों में शामिल थे। एक दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य पुलिस बल के समक्ष आने वाली कठिनाइयों के बारे में पूरी जानकारी देना था, साथ ही कुशल केस हैंडलिंग और साक्ष्य प्रबंधन के लिए ब्लॉक चैन और AI के संभावित उपयोगों के बारे में भी जानकारी देना था।



सीडीटीआई, चंडीगढ़ में आयोजित क्षेत्रीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस की समूह फोटो

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के सहयोग से विभिन्न हितधारकों द्वारा नए आपराधिक कानूनों और जेल कल्याण पर प्रशिक्षण का आयोजन

नये आपराधिक कानूनों और जेल कल्याण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम एक पहल थी जिसका उद्देश्य कानून प्रवर्तन और सुधार कार्मिकों के कानूनी ज्ञान और पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाना था। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य नए अधिनियमित आपराधिक कानूनों— भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023 के बारे में गहन जानकारी प्रदान करना था। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम में जेल प्रशासन, नैतिक शासन और सुधार कर्मचारियों के लिए मनोवैज्ञानिक कल्याण में उत्तम कार्य प्रणालियों पर जोर दिया गया। 'नए आपराधिक कानून 2023 पर जेल अधिकारियों का संवेदीकरण' पर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा निम्नलिखित तीन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए:

- (1) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, पासीघाट परिसर के सहयोग से 25 प्रशिक्षुओं के लिए दिनांक 03-07 मार्च, 2025 तक पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।
- (2) जेल कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर, कर्नाटक के सहयोग से दिनांक 11 से 13 फरवरी 2025 तक जेल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 20 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
- (3) ओडिशा कारागार विभाग के सहयोग से महात्मा गांधी कारागार एवं सुधारात्मक सेवा अकादमी, छताबार, भुवनेश्वर, ओडिशा में दो जेल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए। पहला कार्यक्रम दिनांक 8 से 10 जनवरी तक और दूसरा दिनांक 15 से 17 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया। इसमें कुल 20 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।



महात्मा गांधी कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं अकादमी, छताबार, भुवनेश्वर में उपस्थित अधिकारीगण



जेल कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर, कर्नाटक में पाठ्यक्रम के दौरान जेल अधिकारी

From the desk of Director General.....

I am pleased to present the Jan-March 2025 volume of the BPR&D Quarterly News Bulletin, capturing the wide array of impactful initiatives and meaningful engagements undertaken by the Bureau and its training centers in the quarter.

On 8th January 2025, the Hon'ble Union Home Minister and Minister of Cooperation, Sh. Amit Shah visited the BPR&D HQ and reviewed the working of the organization. He outlined his vision to enhance the projection, utility and evolution of BPR&D as the robust and reliable think tank for MHA, supporting the police organisations of the country. BPR&D has initiated action in the right earnestness to fulfil the mandate given by Hon'ble Union Home Minister.

Other notable capacity building activities in the month of January were conduct of Seminar on Quantum Computing underlining our intent to integrate frontier technologies in policing, Prison Training courses for sensitization of Prison Officials on New Criminal Laws 2023 in Orissa, Karnataka and Arunachal Pradesh. Bureau also organised 5th Half yearly Meeting of Narakas, as per directives of Official Language Department, MHA.

The month of February saw conduct of the Regional Police Science Congress at various training institutes of BPR&D, which aimed to identify and deliberate on the policing challenges. Regional Conference on Artificial Intelligence in Policing, Workshop on revision of SOP for Coastal Police Stations, Space Technology Application based course, Workshop on Anti Human Trafficking and Course on handling of digital evidence were the other salient activities undertaken by BPR&D.

During the month of March, the Bureau organised salient events, which include - National & Internal Security module for 78th batch of IRS, Workshop for establishment of Prosecution Directorate, meeting on recommendation no.14 of DGPs/IGPs conference 2024, the Indigenization of band instruments used by Police Bands.

I extend my heartfelt appreciation to all the officers, experts, and participants who contributed to the success of these initiatives. As we move forward, let us continue to strive for the excellence in policing research, innovation, and public service, guided by the core values of integrity, empathy, and professionalism.

Director General
Bureau of Police Research and Development

SHRI AMIT SHAH, UNION HOME MINISTER AND MINISTER OF COOPERATION REVIEWS THE FUNCTIONING OF BPR&D

Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah chaired a review meeting of BPR&D on 08.01.2025. Sh. Rajeev Kumar Sharma, DG, BPR&D briefed on the activities and ongoing/ completed tasks of BPR&D and proposed the way forward. UHM shared his vision and gave directions on certain issues.

He desired that concept of Green Jail be implemented as part of Model Jail. He stressed to create a structure comprising BPR&D, NCRB, and officers from prisons and forensic psychologists in the Modus Operandi Bureau. The impact of the cybercrime prevention scheme against women and children should also be studied.



He further emphasised on standardization of police stations and identification of key areas for uniformity, developing a model law for CCTV regulation and sharing of data with central agencies and from various states. Underlining the importance of new criminal laws, he exhorted to lay focus on increasing the use of technological evidence, reducing reliance on witnesses, and expediting trials.

He urged building network with technical institutions to facilitate studying and seeking solutions to challenges to policing and in the process to evolve as an important think tank for government.



He highlighted the need for staying informed of global trends in policing, investigation, and prosecution. He suggested collaborations with foreign institutions for R&D and desired alignment between the Home Ministry's agenda and national policing needs ensuring concrete action on the same.



COLLABORATION BETWEEN USI AND BPR&D



DG, BPR&D Presenting a Memento to Director General, United Service Institutions of India (USI), New Delhi

A meeting was held on 10.01.2025 at BPR&D HQ. between Sh. Rajeev Kumar Sharma, IPS, DG, BPR&D and Maj. Gen. BK Sharma, Director General, United Service Institutions of India (USI), New Delhi, to establish collaboration with USI. ADG, BPR&D, Director (NPM), Dy. Director (Training), and Dy. Director (Admn. & R&CA) and officers from USI participated in the meeting. United Service Institution of India (USI) is a national security and defence services think tank based in New Delhi.

As per discussion on potential collaboration, the United Service Institution of India (USI) has been requested to submit a detailed proposal to BPR&D to pave way for collaboration and conduct of courses on national and international security issues.

MEETING ON “ORGANISATIONS WORKING IN THE FIELD OF POLICE RELATED CHALLENGES AND TECHNOLOGIES” AT BPR&D

A hybrid meeting was held under the Chairmanship of Sh. Rajeev Kumar Sharma, DG, BPR&D on 10.01.2025 at Bureau Headquarters, in which representatives from C-DAC, IIIT Allahabad, DRDO (Low Intensity Conflicts), SVPNPA, NEPA & TISS, Mumbai and Directors of all Divisions of Bureau Headquarters also participated. The meeting discussed possible areas of future cooperation/ collaboration with police institutions and organizations related to challenges and technologies in functioning of Police forces.



DG, BPR&D chairing the meeting at BPR&D Headquarters

DRONE SIMULATION EXERCISE DURING THE DSI COURSE ON CYBER CRIME INVESTIGATION

CDTI, Chandigarh conducted a DSI Course on Cyber Crime Investigation from 30.12.24 to 10.01.25, in which 27 Police officers from the rank of SI to Dy. SP from the client states participated. Sessions on Digital evidence handling and extraction of the data from the digital devices, introduction to Drone systems, and practical simulation on procedure to extract the requisite information from the Drone system were conducted. The participants also visited CFSL- Computer Forensic Division for the demonstration of the forensic tools.



Participants during outdoor session of Drone Simulation Exercise

During the 02-week course, 02 eminent faculties, namely Sh. Mukesh Chaudhary, Cyber Expert, Jaipur and Sh. Nisheet Dixit, Adv.& Cyber Expert, conducted sessions on the Networking- VPNs/Proxy servers, VOIP, Information gathering virtual computer crimes and cyber patrolling, Information Technology Act & challenges faced in dealing with digital evidence and its admissibility in the courts.

FIFTH HALF-YEARLY MEETING OF NARAKAS, SOUTH DELHI-1



ADG addressing the Participants during the meeting

In the meeting, members discussed the work being done in Hindi at their offices. Dr. Vandana Sharma, Deputy Director of the National Malaria Research Institute, gave a presentation detailing the efforts being made in her office to promote the official language.

In his chairman's address, Sh. Ravi Joseph Lokku, Additional Director General, encouraged the member offices to present the best practices being adopted for the promotion of the official language in their offices at the next meeting and awarded the winners of Hindi competitions organized by member offices to boost their morale.

The BPR&D presently heads NARAKAS, South Delhi-1 as designated by the Official Language Department of the Ministry of Home Affairs, under which there are a total of 75 member offices. As per the mandate given by the MHA, the Chairman's Office has to organize two half yearly meetings in a year.

In line with this fifth half-yearly meeting of NARAKAS was organized at the Bureau Headquarters on 22.01.2025 under the chairmanship of ADG, BPR&D, in which a total of 124 office heads / representatives from member offices participated.



ADG, IG(SPD), DIG (SPD) and Joint Director, MHA during NARAKAS meeting

SEMINAR ON “WHAT SHOULD I TELL MY CONSTABLE ABOUT QUANTUM COMPUTING & SHOULD I”

The Seminar “What Should I tell My Constable About Quantum Computing & Should I” was conducted by CDTI, Jaipur on 30.01.25, engaging 200 participants, including police personnel, legal trainees, and students from Manipal University and JK Lakshmipat University.

Experts discussed quantum computing fundamentals, its potential impact on cybersecurity, encryption, and digital forensics, and whether law enforcement should be concerned or prepared for its advancements.

The seminar highlighted how quantum computers could break classical encryption, posing risks to secure communications and sensitive data protection. Speakers also delved on the potential benefits, such as faster data analysis, improved predictive policing, and enhanced cryptographic solutions to counter cyber threats.



Director, CDTI Jaipur delivering his points during the seminar

REVISION OF SOP FOR COASTAL POLICE STATIONS

On 03.02.2025, a Hybrid meeting was held at BPR&D HQ regarding the drafting of SOP for Coastal Police Stations, which was presided over by ADG, BPR&D. Senior officers from BSF and BPR&D participated in the meeting. The discussions were held about the role of the BSF Water Wing and coordination with Coastal Police Stations.

The role of the water wing of BSF and its deployment in the Sundarbans Area in West Bengal and Sir Creek Area in Gujarat, coordination with the Coastal Police and communication plan with the Coastal Police, Indian Coast Guard and Indian Navy was included in the Revised SOP for Coastal Police. In the series, the second workshop held on 06.02.2025 discussed with all stakeholders on finalizing the SOP for Coastal Police Stations of India. The points which emerged during the workshop were incorporated in the revised SOP for Coastal Police Stations.



Officials attending the meeting at BPR&D HQs, presided by ADG, BPR&D

AWARENESS PROGRAMMES FOR SCHOOL CHILDREN



The participants of the Awareness Programme

On 11.02.25, CDTI, Hyderabad conducted the awareness programme "How to report incidents of misbehaviour (Good touch-Bad touch)" for students of KV-II Uppal, Hyderabad, with 76 girl students and 02 teaching staff participating. The objective of the awareness programme was to sensitise children and young adults in distinguishing between safe and dangerous physical touch. The programme

helped kids understand their bodies, create personal boundaries, and speak up when they feel uncomfortable or dangerous.

BPR&D ORGANIZES WORKSHOP ON 'ANTI-HUMAN TRAFFICKING' (AHT)

On 14.02.25, 30 officers from different states, UTs, CAPFs, CPOs, and representatives from the Ministry of Women and Child Development/National Commission for Women and National Commission for Protection of Child Rights participated in a workshop on Anti Human Trafficking presided by Shri Ravi Joseph Lokku, ADG, BPR&D. Shri P.M. Nair, a subject matter expert, suggested that stakeholders should receive appropriate training with an emphasis on the Attitude, Skill, and Knowledge (ASK) model. He also underlined the necessity of treating AHT instances as organized crimes, establishing connections between states for the sake of inquiry, and making sure that the qualifications of NGOs are properly verified prior to signing the MOUs. He also opined that the MOUs with NGOs should be for one year.



Shri Rajeev Kumar Sharma, IPS, DG, BPR&D graced the workshop and gave valedictory remarks

COURSE ON “HANDLING OF DIGITAL EVIDENCE IN CASES OF ECONOMIC OFFENCES & CORRUPTION CASES”

CDTI Chandigarh hosted a 5-day course on “Handling of Digital Evidence in Cases of Economic Offences & Corruption Cases” from 17.02.25 to 21.02.25. The course covered topics such as volatile memory in digital forensics, investigation of payment gateways, hashing, imaging, metadata analysis, appreciation of digital evidence in economic crimes, banking, etc. with case laws, drone surveillance, and infiltration of traces pertaining to drone infiltration. Practical sessions on social media crimes and proxy servers were also conducted. Cyber-Expert Sh. Mukesh Chaudhary delivered a session on VPN/proxy servers and virtual numbers. DCP, Panchkula, Ms. Himadri Kaushik, IPS presided over the valedictory session and shared her experience with the trainee officers.



Director, CDTI, Chandigarh presenting a memento to DCP, Panchkula, Ms. Himadri Kaushik

REGIONAL CONFERENCE ON “ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN POLICING”

CDTI, Hyderabad conducted a Regional Conference on Artificial Intelligence from 18.02.25 to 19.02.25. Commissioner of Police, Hyderabad City, Shri C.V. Anand, IPS inaugurated the Conference. He highlighted the role of Artificial Intelligence and how Artificial Intelligence is transforming industries across the globe, enhancing efficiency, and enabling faster, data-driven decisions. He delved on the transformative potential of AI and the India AI Mission, a landmark initiative aimed at catalyzing India's AI ecosystem, which is designed to not only boost research and innovation but also establish India as a key player in shaping the global AI landscape.



Chief Guest, Shri CV Anand, IPS

The conference featured guest faculty from IIT-Hyderabad, ISB-Hyderabad, CEOs of AI industry companies, and IPS officers from Andhra Pradesh Police and C-DAC. Shri Amit Garg, IPS, the Chief Guest of Valedictory Session highlighted the recent Artificial Intelligence Action Summit in France, where the Prime Minister called for a governance model to address threats of deep fakes, disinformation, and cybersecurity.



Group Photograph of the participants of Regional Conference on 'AI' held at CDTI, Hyderabad

INDIGENISATION OF BAND INSTRUMENTS USED BY POLICE BAND

A workshop was held at BPR&D HQ in New Delhi on 19.02.2025 to study the indigenization of band instruments used by the CAPFs/Police Band. The committee, consisting of members from CAPFs and BPR&D, was constituted to further study band equipment and submit recommendations on the feasibility of indigenization.

On 06.03.2025, the committee visited Meerut to interact with band manufacturing companies. The study focused on the quality of Indian-made musical instruments for police brass and pipe bands and explored the possibility of manufacturing such equipment in India.

On 19.03.2025, another workshop held at BPR&D Hqrs. took stock of band instruments used by the CAPFs/Police Band and the way forward towards indigenisation. Manufacturers showcased their Indian-made equipment, and feedback was obtained from bandmasters. A number of equipments that can be manufactured as 'Make in India' were shortlisted for further deliberations and action.



Workshop at BPR&D HQ



Visit of Committee to band manufacturing company at Meerut

REGIONAL POLICE SCIENCE CONGRESS WORKSHOP ORGANISED

A one day Regional Police Science Congress Workshop was organized on 20.02.2025, aimed to identify the problems and challenges faced by law enforcement agencies and to gather suggestions for effective solutions.

Officers from the client States of CDTI, Hyderabad—Telangana, Puducherry, Kerala, Maharashtra, Andhra Pradesh, and Karnataka—actively participated in the workshop and highlighted the key issues and challenges encountered by their law enforcement agencies, along with proposed



DGP Telangana State, Dr. Jitender, IPS, addressing the participants

solutions to address these challenges effectively, through power point presentations.

DGP, Telangana State, Dr. Jitender, IPS, the Chief Guest, in his valedictory address commended the efforts of BPR&D and CDTI Hyderabad for organizing the workshop, which provided a valuable platform for officers from the rank of Sub-Inspector to Deputy Superintendent of Police, to discuss the challenges faced and proposed remedies.



Group Photograph of Participants in Regional Police Science Congress

SPACE TECHNOLOGY APPLICATION BASED COURSE

The 8th three-day Space Technology Application Based Course was conducted from 19.02.25 to 21.02.25 at BPR&D HQ New Delhi. Total 18 Participants from different states/UTs participated in the programme. So far, 07 Space Technology Application Based Programmes have been organized, and 200 police officers have been trained on various themes of Space Applications in Internal Security.

The programme was inaugurated by Director (Training), BPR&D. Dy. Commandant, SSB, Dr. Ajay Kumar Sharma, faculty spearheaded the training sessions.



Participants in Space Technology Application Based Course

REGIONAL CONFERENCE ON CHALLENGES FOR POLICING & RE-CONCEPTUALIZING THE ALL INDIA POLICE SCIENCE CONGRESS



A memento presented to the speaker during the conference

On 21.02.25, two significant events were conducted by CDTI, Jaipur to address key issues in policing and enhancing legal awareness among students.

A Regional Conference titled "Challenges for Policing & Re-conceptualizing All India Police Science Congress" was organized to discuss modern challenges in policing, public safety, community relations, and crime prevention based on the decisions of All-India Police Science Congress (AIPSC), an annual event under the BPR&D.

Same day, an awareness programme on New Criminal Laws and Cyber Safety was conducted at

Biyani Law College in Jaipur. This programme, attended by around 400 students, aimed to educate participants about recent developments in criminal law and cyber safety in the digital age.

WORKSHOP ON STANDARDIZATION OF TRAINING FOR THE DIRECTLY RECRUITED RANKS OF CIVIL POLICE

The draft syllabi of directly recruited ranks of civil police was developed and presented to the Hon'ble Union Home Minister on 3rd January 2025. The Home Minister had directed the committee to organize six workshops and present the draft syllabi to the States/UTs for feedback and finalization.

In the follow up, the Apex Committee held a two-day consultative workshop on the standardization of training for the Directly Recruited Ranks of Civil Police in Northern



Workshop on Standardization of Training for the Directly Recruited Ranks of Civil Police

States/UTs on 27.02.25 to 28.02.25 at BPR&D HQ, under the Chairmanship of Sh. K. Vijay Kumar, IPS (Retd).

The workshop involved senior police officers, retired officers, and representatives from various states/UTs/CAPFs.

INTER-COLLEGIATE COMPETITION ON NEW CRIMINAL LAWS

In terms of recommendations of the DGsP/IGsP Conference, CDTI, Hyderabad organized an Inter-Collegiate Competition aimed at generating awareness among law students about new criminal laws through video presentations.

Students from law colleges, namely College of Law, Osmania University, Padala Rami Reddy Law College, Keshav Memorial Law College, Peendekanti Law College, Anantha Law College, and College of Law for Women, Andhra Mahila Sabha participated. 87 teams registered for the event and themes were assigned through a lottery system. The top 15 videos were awarded cash prizes and trophies, while teams ranked 16th to 20th received consolation prizes. All participants were also presented with appreciation letters. The Valedictory Ceremony was graced by Hon'ble Justice Shri C.V. Ramulu (Retd.), who commended the Central Government's efforts in promoting awareness about New Criminal Laws and praised the enthusiasm and creativity of the students.



Director, CDTI, Hyderabad addressing the participants

NATIONAL & INTERNAL SECURITY MODULE FOR 78TH BATCH OF IRS OFFICERS (OT)

The CDTI, Ghaziabad conducted a course on the National & Internal Security Module for IRS (OT) officers from 11.03.2025 to 12.03.2025. The course was attended by 144 IRS (OT) officers and faculty included Shri O. P. Singh, Ex-DGP UP, Maj Gen (retd.) Deepak Mehra, and Col (Retd.) Nitish Bhatnagar.

On 12.03.2025, Sh. Rajeev Kumar Sharma, IPS, DG, BPR&D, in his valedictory address to the IRS trainee officers, provided valuable insights into the complexities of national security. Emphasising on the security of the country, he said that "Security of the land cannot be addressed in isolation—whether internal, financial or any other dimension of security. These aspects are interdependent, with developments in one area inevitably impacting the others. Thus holistic perspective is essential for comprehending the multifaceted nature of security in our country."

The two-day course featured six sessions, with Maj Gen (retd.) Deepak Mehra providing an in-depth discourse on national security, Shri Jitendra Singh offering a comprehensive analysis of I4C, Dr. Sandip Beniwal discussing funding of terrorism, and Shri Honey Patodi, Dy Director of FIU India, discussing fake currency notes and white collar crime. Col (Retd.) Nidhish Bhatnagar discussed AI & national security, and Shri O.P. Singh, (Ex-DG), provided a detailed exposition on internal security challenges in India.



Sh. Rajeev Kumar Sharma, IPS, DG, BPR&D, in his valedictory address to the IRS trainee officers

WORKSHOP FOR ESTABLISHMENT OF PROSECUTION DIRECTORATE

A one day workshop in hybrid mode was organized for Establishment of Prosecution Directorate at BPR&D HQ on 25.03.2025 under the Chairmanship of DG BPR&D. ADG, BPR&D, Director (Training), senior officials from BPR&D, Officials and Representatives from Prison/Legal Department from States/UTs participated in the workshop.

Issues & Challenges for establishment and functioning of Prosecution Directorate as per Section 20 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita and challenges in implementation of New Criminal Laws w.r.t Judiciary and Prosecution were discussed.



Officials attending Workshop for Establishment of Prosecution Directorate

HINDI WORKSHOP



Bureau's officials during workshop

In compliance of the annual programme issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, a Hindi workshop was organized on 27.03.2025 at the Bureau Headquarters. In the workshop challenges faced by the personnel of Bureau while attending to the day-to-day work of the office in Hindi were resolved. Mrs. Veenu Khanna, Assistant Director, Department Official Language, Ministry of Home Affairs, addressed the participants present in the workshop.

MEETING ON RECOMMENDATION NO. 14 OF DGsP/IGsP CONFERENCE 2024

A meeting on Recommendation No. 14 of DGsP/IGsP Conference 2024 i.e. "Every week, visitors, including school children could be invited to the local police station for an exposure to the various equipment and records in the PS" was held on 27.03.25 at Bureau HQ. The meeting chaired by Ms. Ruchika Rishi, IG/Director (NPM) discussed that, debates could be organised in schools and colleges on the types of work undertaken by the Police.



Director, National Police Mission, BPR&D addressing the participants

Total 11 officers of various States/UTs participated in the meeting. Ongoing Practices which are currently running in States/UTs and future road maps were discussed during the meeting in order to prepare an advisory to assist States/UTs in implementation of the recommendation.

CDTI CHANDIGARH ORGANISES 'REGIONAL POLICE SCIENCE CONGRESS'

CDTI, Chandigarh, organized a One-day Regional Congress on 31.03.2025, which was attended by 54 police officers (Constable to Dy.SP). The Congress focused on the recommendations of 50th AIPSC and discussed New Criminal Laws (NCLs), AI and Cyber Crimes, and the use of forensics and technology to ensure accountability, transparency, and speedy justice. The significance of Zero FIR and e-FIR, NCL timelines, community policing, police as first responders in disaster risk reduction, and combating radicalization in jails were among the main topics of discussion. The congress sought to give a thorough grasp of the challenges faced by the police force as well as the possible uses of Block Chain and Artificial Intelligence for efficient Case Handling and Evidence Management.



Group Photograph of the Participants of the Regional Police Science Congress held at CDTI, Chandigarh

TRAINING ON NEW CRIMINAL LAWS AND PRISON WELFARE ORGANIZED BY VARIOUS STAKEHOLDERS IN COLLABORATION WITH THE BPR&D

BPR&D in collaboration with various stakeholders organised the training programme aimed at enhancing the legal knowledge and professional capabilities of law enforcement and correctional personnel. This training sought to provide in-depth insights into the newly enacted Criminal Laws—Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), and Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA), 2023. Additionally, the programme emphasized best practices in prison administration, ethical governance, and psychological well-being for correctional staff. The following three courses were conducted on 'Sensitization of Prison Officials on New Criminal Laws 2023':

- (1) Rashtriya Raksha University, Pasighat Campus, organised a Five-day Training programme from 03.03.25 to 07.03.25 with 25 trainees.
- (2) Prison Staff Training Institute, Mysuru, Karnataka conducted course for prison officers from 11.02.25 to 13.02.25 in which 20 officers were trained.
- (3) Odisha Prison Department conducted Prison Training Courses at the Mahatma Gandhi Academy of Prisons and Correctional Services, Chhatabar, Bhubaneswar, Odisha in two batches, one from 08.01.25 to 10.01.25 and the other from 15.01.25 to 17.01.25. A total of 20 officers were trained.



Prison Officials attending Course at Mahatma Gandhi Academy of Prisons & Correctional Services, Chhatabar, Bhubaneswar.



Session at Prison Staff Training Institute, Mysuru, Karnataka



International Year
of Cooperatives

Cooperatives Build a Better World



बीपीआरएंडडी मुख्यालय में तमिलनाडु पुलिस अकादमी के १२वें बैच के उप पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षुओं का दौरा

Visit of the 12th Batch of Dy. SP Trainees of Tamil Nadu Police Academy to BPR&D Headquarters



011- 26782012



BPRD India



indiabprd



officialBPRDIndia



Bureau of Police Research
& Development India



www.bprd.nic.in

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर

नई दिल्ली – 110037

भारत

Please Scan the QR Code to
Subscribe to Youtube Channel

